

दीपावली से पहले बस्तर को सड़क विकास की बड़ी सौगात, 485 बसाहटों को मिलेगी बारहमासी सड़कें

जगदलपुर/जनता के गोठ
रायपुर, 29 अक्टूबर 2026/ दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृत मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा बस्तर संभाग की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की आवश्यकताओं तथा सड़क एवं पुल संपर्क के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए विशेष पहल करने के लिए आग्रह किया था, जिसपर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र द्वारा सकारात्मक रुख प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में बस्तर में सड़क संपर्क विस्तार की प्रगति, स्वीकृत कार्यों, प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों तथा विशेष छूट के संबंध में की जा रही कार्यवाही की



अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बैच-2 के अंतर्गत 280 बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 804.06

सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर जिले की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोण्डागांव की 34 तथा सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं।
754 और बसाहटों तक पहुंचेगी बारहमासी सड़क, सातों जिलों में प्रस्ताव तैयार- पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे बैच में बस्तर जिले की 114, बीजापुर की 125, दंतेवाड़ा की 63, कांकेर की 140, कोण्डागांव की 31, नारायणपुर की 136 और सुकमा की 146 बसाहटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप द्वारा सर्वे के साथ गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का काम भी

किया जा रहा है। इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से विशेष रूप से अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाजारों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे।
पुल निर्माण को भी मिलेगी गति, 373 पुलों के प्रस्तावों पर हुई चर्चा- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में बताया है कि पीएमजीएसवाई-4 के बैच-1 के अंतर्गत 206 पुलों तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर विचार करने

के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग के लिए 55 लंबे पुलों के प्रस्ताव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगामी चरणों के लिए भी पुल निर्माण की कार्ययोजना तैयार की गई है। नारायणपुर जैसे दुर्गम जिले में पीएम-जनमन के अंतर्गत 22 लंबे पुलों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 87.45 करोड़ रुपए है। इन पुलों के निर्माण से वर्षा ऋतु में नदी-नालों के कारण कट जाने वाले गांवों को बड़ी राहत मिलेगी तथा दूरस्थ बसाहटों के लिए आवागमन सुगम हो सकेगा।

भिलाई में ‘सांसद-सरपंच संवाद’ का आयोजन : वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर राजू वर्मा ‘सांसद गौरव सम्मान’ से सम्मानित



भिलाई में आयोजित ‘सांसद-सरपंच संवाद’ कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस विशेष समारोह में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वाले लोगों को ‘सांसद गौरव सम्मान’ से नवाजा। इस कड़ी में पाटन के प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और पक्षी विशेषज्ञ राजू वर्मा को ‘सांसद गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान पर्यावरण, विशेषकर पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए

दिया गया है।
वेटलैंड और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर विशेष कार्य
राजू वर्मा लंबे समय से क्षेत्र में वेटलैंड्स (आद्रभूमि) और पक्षियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आने वाले विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों (माइग्रेटरी बर्ड्स) की अद्भुत फोटोग्राफी की है और उनके रहवास को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके इसी समर्पण और उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए सांसद विजय बघेल ने उन्हें मंच पर सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य

की शुभकामनाएं दीं।
इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सभापति नीलम चंद्राकार, जनपद अध्यक्ष कीर्ति नायक, उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा, सांसद प्रतिनिधि राजा पाठक, राजेश चंद्राकार,सरपंच रवि सिंगौर, सरपंच अध्यक्ष विनय चंद्राकार, रूपेंद्र शुक्ला,नगर पंचायत अध्यक्ष अध्यक्ष दयानंद सोनकर,, सरपंच झोट राजू साहू सहित अन्य सरपंच और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिन्होंने राजू वर्मा की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है।



अधिकारी के सामने रिंगनी ग्राम सचिव खडानंद वर्मा के द्वारा संयोजक तहसीलदार महोदय को सुपुर्द किया गया वहीं 2:00 बजे केसदा गांव में बैठक की निर्धारित समय रखी गई थी जिस पर 3 घंटे बाद 5:00 बजे बैठक पर आला अधिकारी एवं संयोजक अनुराग भट्ट ग्राम पंचायत भवन केसदा पहुंचे पंचायत भवन में ग्राम सरपंच सचिव प्रभावित किसान तथा गांव के लोग बड़ी संख्या में पहले से इंतजार कर रहे थे अधिकारी जैसे ही पंचायत भवन में पहुंचे उपस्थित ग्रामीणों के साथ संयोजक तहसीलदार अनुराग भट्ट की कहां सनी शुरू हो गई गांव के लोग बैठक में लड़ते रहे, बैठक के 15 मिनट बाद ही अनुराग भट्ट संयोजक तथा आला अधिकारी वहां से चले गए तथा किसी भी प्रकार का नतीजा नहीं निकल पाया
पंचायत के जिम्मेदारों को ही सोशल मीडिया से मिली

बजाय रायपुर के अखबार में प्रकाशित कराया गया। ऐसे में स्थानीय स्तर पर सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रभावित हुआ। सवाल उठ रहा है कि जब जमीन बलौदाबाजार जिले के किसानों की प्रभावित होनी है और जनसुनवाई सिमचार माध्यमों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? कौन से अखबार में प्रकाशन हुआ था उनकी भी पुष्टि को लेकर स्पष्टीकरण नहीं है और रायपुर जिला से प्रकाशन करना क्या सही है
प्रभावित हितग्राही, लेकिन सूचना और मुनादी का अभाव!- रिंगनी केसदा के प्रभावित हितग्राही इस भूमि अर्जन प्रक्रिया से जुड़े हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी गई। गांव के कोटवार के माध्यम से मुनादी भी नहीं कराई गई और न ही पटवारी द्वारा किसानों को जानकारी दी गई। ग्रामीणों को अखबार की कटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसुनवाई का पता चला। लेकिन शासन के द्वारा जांच दल गठित कर दिया गया लेकिन प्रभावित निजी भू स्वामी ग्रामीण किसानों को सूचना नहीं दिया गया ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी सफलता: 4.5 किलो के स्वस्थ शिशु की नॉर्मल डिलीवरी

कमल खट्टे/जनता के गोठ
बिरा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरा में 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 3:57 बजे एक बड़ी सफलता दर्ज की गई। देवरहा गांव निवासी राजकुमारी पटेल (उम्र 27 वर्ष) पति मोहर लाल पटेल ने 4.50 किलोग्राम वजन के स्वस्थ पुरुष शिशु को सामान्य प्रसव (नॉर्मल डिलीवरी) के माध्यम से जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इतने अधिक वजन के शिशु की नॉर्मल डिलीवरी को चिकित्सकीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जिसे बिरा पीएचसी की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस सफल प्रसव में डॉ.



जाहид अंसारी प्रतापपुर। प्रदेश में चक्रवाती तूफान के प्रभाव से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के कारण धान, मक्का सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। खेतों में खड़ी और कटाई के लिए तैयार फसलों पर मौसम की मांग से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संभागीय महासचिव चन्द्रदीप कोचों ने प्रदेश सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने और नुकसान का आकलन करकार किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
चन्द्रदीप कोचों ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत कर अपनी



शौघ राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने मांग की कि राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम गठित कर प्रभावित गांवों में खेतों का सर्वे कराया जाए। धान, मक्का एवं अन्य फसलों को हुए वास्तविक नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर पात्र किसानों को नियमानुसार शौघ मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके।
चन्द्रदीप कोचों ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए सरकार को बिना अनावश्यक देरी के उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

कोलावल हाई स्कूल मैदान में बस्तर ओलंपिक का आयोजन, 14 खेल विधाओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

दो दिवसीय प्रतियोगिता में नौ गांवों के बालक-बालिकाओं ने लिया हिस्सा, खेल भावना और उत्साह के साथ किया प्रतिभा का प्रदर्शन

भुजबल बघेल
बकावंड (जनता के गोठ)। विकासखंड बकावंड अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल कोलावल के खेल मैदान में दो दिवसीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे बालक एवं बालिकाओं ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।



दो दिनों तक आयोजित इस खेल महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो-खो, दौड़ सहित कुल 14 खेल विधाओं में मुकाबले आयोजित किए गए। बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खेल मैदान में

खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस प्रतियोगिता में पाथरी, मैलबेड़ा, कोलावल, मोखागांव, भिरंडा, धनपुर, चोकनार, छिंदगांव एवं सिदावंड सहित आसपास के गांवों के खिलाड़ियों ने सहभागिता निभाई। ग्रामीण अंचल के बच्चों और युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला।
आयोजन के दौरान विशालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं

खेतों में लहलहा रही धान की फसल, सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य; सैकड़ों किसानों के सामने धान बेचने का संकट

गिरदावरी में चूक से किसान पेशान, तहसील और एसडीएम कार्यालय के लगा रहे चक्कर; पोर्टल खुलने के बाद ही समाधान की उम्मीद

जाहिद अंसारी, सूरजपुर।
प्रतापपुर। खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में किसानों का रकबा शून्य दर्ज है। गिरदावरी में कथित लापरवाही का खामियाजा अब प्रतापपुर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के सामने अब अपनी उपज बेचने का संकट खड़ा हो गया है। समस्या के निराकरण के लिए किसान लगातार तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल पाई है।
जानकारी के अनुसार, प्रतापपुर विकासखंड के दर्जनों गांवों में किसानों के खेतों में धान की फसल होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड और पोर्टल में फसल का रकबा शून्य दर्ज होने की शिकायत सामने आ रही है। किसानों का कहना है कि गिरदावरी के दौरान हुई चूक के कारण उनकी वास्तविक फसल का



विवरण दर्ज नहीं हो पाया। अब जब धान बेचने का समय आया है, तो पोर्टल में रकबा दर्ज नहीं होने से उन्हें धान विक्रय में पेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तहसील और एसडीएम कार्यालय के काट रहे चक्कर- समस्या के समाधान के लिए प्रभावित किसान लगातार तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आवेदन दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें कभी गिरदावरी में त्रुटि तो कभी पोर्टल

भौतिक सत्यापन कर रकबा दर्ज करने की मांग- प्रभावित किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि खेतों में लगी धान की फसल का तत्काल भौतिक सत्यापन कराया जाए। वास्तविक स्थिति के आधार पर गिरदावरी में सुधार कर पोर्टल पर किसानों का सही रकबा दर्ज किया जाए, ताकि कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे। साथ ही गिरदावरी में हुई कथित लापरवाही की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खेतों में धान की फसल मौजूद है और किसान धान बेचने के लिए तैयार हैं, तो केवल सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य होने के कारण उन्हें अपनी उपज बेचने से क्यों जूझना पड़ रहा है? शासन-प्रशासन कब तक पोर्टल खुलने का इंतजार कराएगा और प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए समय रहते क्या कदम उठाएगा?

बंद होने का हवाला देकर वापस लौटा दिया जाता है। ऐसे में किसानों की पेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। महीनों की मेहनत और खेती में लगाई गई पूंजी के बाद भी यदि किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए, तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
रोजाना आ रहे सैकड़ों किसानों के आवेदन : तहसीलदार- इस समय के तहसीलदार सुरेश राय ने बताया कि प्रतिदिन इस तरह की शिकायतें

सामने आ रही हैं और सैकड़ों किसानों के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर सूरजपुर कलेक्टर से चर्चा की जा रही है। पोर्टल फ्लिहाल बंद होने के कारण सुधार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। शासन से पोर्टल खोलने और समस्या के निराकरण के संबंध में निर्देश मिलने के बाद ही प्रभावित किसानों की समस्या दूर हो सकेगी। कलेक्टर के दिशा-निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट न मिलना यही बताता है कि वह अपनी दयनीय दशा से उबरने में नाकाम है। इन चार राज्यों से से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में तो अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसके कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से कोई भी नहीं जीत सका। विधान परिषद सदस्यों यानी एमएलसी के लिए हुए इन चुनावों के वोटर शिक्षक एवं स्नातक थे। कांग्रेस जिस तरह अपने शासन वाले कर्नाटक में भी सभी चारों सीटें हार गई, वह उसके लिए कहीं अधिक शर्मनाक है। बिहार और महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दलों को तो सफलता मिली, लेकिन वह अपना खाता नहीं खोल सकी। बिहार में नई बनी जन सुराज पार्टी के एक प्रत्याशी के साथ एक निर्दलीय भी एमएलसी बन गया, लेकिन राजद और भाकपा-माले लिबरेशन जैसे सहयोगी दलों के बाद भी कांग्रेस को नाकामी हाथ लगी। यह नाकामी यही बताती है कि कांग्रेस न तो प्रबुद्ध शिक्षकों को प्रभावित कर पा रही है और न ही स्नातकों को। भले ही स्नातक और शिक्षक वोटरों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन वह इतनी कम भी नहीं होती कि कोई दल उन्हें महत्व न दे। आज शिक्षक लोगों के बीच जनमत तैयार करने का काम करते हैं, वहीं स्नातक आम तौर पर जल-पाँत से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। यदि कांग्रेस इन वर्गों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही है तो इसके लिए वह अपनी रीति-नीति के अतिरिक्त अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। कांग्रेस को यह समझ आ जाए तो अच्छा कि वोट चोरी जैसे शिगुण छेड़ने से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस को इसका भी आभास हो जाना चाहिए कि वह ईवीएम पर व्यर्थ ही अपनी खीझ निकाल रही है। वह ईवीएम के बजाय मत पत्रों से चुनाव पर जोर दे रही है। उसे मुंह चिढ़ाने वाला तथ्य यह है कि एमएलसी चुनाव मत पत्रों के जरिये ही हुए। इसी कारण प्रधानमंत्री ने उस पर तंज कसा। मत पत्रों से हुए चुनावों में भी कांग्रेस की विफलता यही सिद्ध करती है कि कांग्रेस जिस तरह एसआइआर को वोट चोरी का नाम देकर लोगों को गुमराह करने के साथ अपना वक्त जाया कर रही है, उसी तरह मत पत्रों से चुनाव कराने की भी बेतुकी मांग कर रही है।

आज का राशिफल

मे़ष राशि : आज का दिन फ़ेवरेबल रहने वाला है। आज आपके ब्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिला सकता है। आज पारिवारिक रिश्ते में गहराई और अपनापन आपको महसूस होगा। वृष राशि : आज का दिन आपके लिए ख़ास होने वाला है। आज आपको बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। आज अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने काम के प्रति एकाग्र वित्त होना आपको सफलता देगा।

मिथुन राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी विशेष आयोजन में जाने का मौका मिलेगा और नई जानकारीयां सीखने को मिलेंगी। आज खर्चों की अधिकता रहेगी। कर्क राशि : आज का दिन आपके लिए टीक-ठाक रहने वाला है। आज आपकी सुझबूझ और विवेक से समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। आज ऑनलाइन शॉपिंग और मस्ती वाली गतिविधियों में समय बीतेगा। सिंह राशि : आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज परिवार संबंधी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह-मशवरा होगा और इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे।

कन्या राशि : आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कार्यवाही में सफलता मिलेगी। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आपको सशक्त महसूस करेंगे। तुला राशि : आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काम जितना भी कठिन हो आपको एकाग्रता बनाये रखना है।

वृश्चिक राशि : आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यावसायिक संपर्कों को और मज़बूत करने का प्रयास करेंगे। आज कारोबार में आपको फायदा होगा।

धनु राशि : आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको वाद-विवाद से दूर रहना होगा। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा।

मकर राशि : आज का दिन आपके लिये अच्छे परिणाम लाने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में अभी और मेहनत करने की जरूरत है। आज घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा।

कुंभ राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी काम को करने के नए तरीके पर विचार करेंगे इससे काम समय से व आसानी से पूरा हो जाएगा। आज शाम को आप किसी बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बनाएंगे।

मीन राशि : आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपकी निजी समस्या सुलझ जाने से मानसिक शांति मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको काम अच्छा चलेगा।

वामपंथियों के शिकंजे में जकड़ी कांग्रेस

राजीव सचान। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी वामपंथ के साथ समाजवाद से भी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी की छवि मध्यमार्गीय दल की बनाए रखी और इसी कारण सभी वर्गों के बीच उसका जनाधार था। इंदिरा गांधी ने भी मध्यमार्ग पर ही चलना पसंद किया। यह बात और है कि एक समय सत्ता बचाए रखने के लिए उन्होंने वामपंथियों का साथ लिया। इसके बदले में उन्होंने शिक्षा एवं आकादमिक संस्थान वामपंथियों के हवाले कर दिए, लेकिन वे जानती थीं कि कांग्रेस की शक्ति मध्यमार्गीय दल बने रहने में ही है। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी ने भी कांग्रेस को मध्यमार्ग में ही रखने की कोशिश की, पर उनके कुछ करीबी वामपंथी भी थे। नरसिंह राव को अपनी अल्टरमत्त सरकार चलाए रखने के लिए वाम दलों का साथ लेना पड़ा, लेकिन वे उनके प्रभाव-बढ़ाव में नहीं आए और इसी कारण देश का कार्याकल्प करने वाले आर्थिक सुधार लागू कर पाए। मनमोहन सिंह को भी वाम दलों का सहयोग लेना पड़ा, लेकिन वे एक सीमा से अधिक उनके दबाव में नहीं आए। उन्होंने अमेरिका से परमाणु समझौते पर वाम दलों के विरोध की परवाह नहीं की। हालाँकि इसी दौर में कांग्रेस अस्थिर सोनिया गांधी की ‘सुपर सरकार’ कही जाने वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में वामपंथियों का बोलबाला था। इस परिषद में जय द्रैव, हर्ष मंजूर, अरुणा राय जैसे वामपंथी रूझान वाले शामिल थे और उनके प्रभाव में मनमोहन सरकार की कई नीतियां भी बनीं। जब घोषित और अपोषित रूप से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में आई तो प्रारंभ में उनके करीबी कांग्रेस के दूसरी पीढ़ी के युवा नेता थे, लेकिन एक-एक करके वे उनका साथ छोड़ गए। इनका स्थान लेना शुरू किया वाम विचार वाले नेताओं ने। अन्ना आंदोलन के समय जिन धुर वामपंथी प्रशांत भूषण ने आंदोलनजीवी के रूप में उभरे योगेंद्र यादव के साथ मिलकर कांग्रेस की ईंट से ईंट बनाते में कोई कसर नहीं छोड़ी, वे आज राहुल के प्रमुख सहयोगियों में से हैं। इन्हीं योगेंद्र यादव ने एक बार कहा था कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए। हाल के वर्षों में राहुल के आसपास वामपंथी विचार वाले नेताओं की जुटाप भी बढ़ी है और कांग्रेस में उनका प्रभाव भी। वामपंथी छात्र नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस में आए लंबा समय हो गया है, लेकिन फिलहाल वे हाशिए पर दिखते हैं। उनकी जगह नई पंरती नेहा बोरा की होती दिख रही है। बीते दिनों राहुल ने वोट चोरी के अपने शिगुण के तहत जो धरना-प्रदर्शन किए, उसमें नेहा को खासी भूमिका रही। नेहा ने कांग्रेस जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन में भी बड़-चढ़कर भाग लिया। राहुल वाम रूझान वाले इस समूह को भी करीब लाने जा रहे हैं। राहुल ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में नेहा और प्रशांत भूषण को बोलने का खास तौर पर अवसर दिया। इससे यही लगा कि उन्हें अपने छात्र संगठन के नेताओं पर उतना भरोसा नहीं, जितना वामपंथी छात्र नेता नेहा पर है।

प्रदूषण के खिलाफ लड़नी होगी साझा लड़ाई

डॉ. दीपक कोहली

सर्दियों की आहट के साथ ही उत्तर भारत के क्षितिज पर छाने वाली गहरी धुंध और धुएँ की परत अब महज एक मौसमी घटनाक्रम तक सीमित नहीं नहीं रह गया, बल्कि यह करोड़ों नागरिकों के लिए एक गंभीर और जानलेवा जन-स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। अक्टूबर से फरवरी के बीच दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) अक्सर 400 से 450 के खतरनाक स्तर को पार कर जाता है।

जैसे ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘खराब’ या ‘गंभीर’ श्रेणी में प्रवेश करता है, प्रशासनिक तंत्र में अचानक अप्रत्याशित गहमा-गहमी दिखाई देने लगती है। आनन-फानन में ग्रेडेड रिसांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के विभिन्न प्रविधानों को लागू कर दिया जाता है। निर्माण कार्यों पर पाबंदी, निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन की तैनाती, डीजल जेनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक और सड़कों पर पानी के छिड़काव जैसे उपाय कागजों और मीडिया की सुर्खियों में तैरने लगते हैं।

जबकि वायुमंडलीय विज्ञान और भूगोल के मौलिक नियमों की दृष्टि से देखें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या केवल एक महानगर या कुछ चुनिंदा जिलों की सीमाओं में सिमटी दंडात्मक और तात्कालिक कार्रवाइयां इस विकराल वायुमंडलीय संकट का वास्तविक और स्थायी समाधान दे सकती हैं? हवा, गैसों और सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5 और पीएम 10) की कोई प्रशासनिक, राजनीतिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती। उत्तर भारत के अनेक



क्षेत्रों के आसमान में तैरने वाला जहर केवल वहां के स्थानीय वाहनों के धुएँ या औद्योगिक चिमनियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पूरे वृहद इंडो-गंगा मैदानी इलाकों के संयुक्त उत्सर्जन और वायुमंडलीय गतिशास्त्र से निर्धारित होता है। ऐसे में किसी एक शहर द्वारा अलग-थलग होकर उठाए गए एकांगी कदम इस बड़े संकट के सामने वैसे ही निष्प्रभावी साबित होते हैं, जैसे उफनती नदी के मुहाने पर पत्तों का बांध बनाना। हालािया वायु गुणवत्ता आंकड़ों का सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण इस भाँति को पूरी तरह से तोड़ देता है कि प्रदूषण केवल दिल्ली-एनसीआर की विशिष्ट समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएम 2.5 का वार्षिक औसत स्तर पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में यह स्तर अक्सर 80 से 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया जाता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में अब अकेले दिल्ली

का नाम दर्ज नहीं है, बल्कि गंगा के मैदानी भूभाग में बसे तमाम शहर इस विषैले चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ से लेकर हरियाणा के रोहतक, हिसार और राजस्थान के औद्योगिक शहर कोटा तक की वायु गुणवत्ता लगातार ‘बेहद खराब’ और ‘अत्यंत गंभीर’ स्तर पर बनी हुई है। उत्तर भारत का एक क्षेत्र भौगोलिक रूप से एक विशाल प्राकृतिक कटोरे के समान है। सर्दियों के आगमन के साथ जब तापमान में गिरावट आती है, तो हवा का घनत्व बढ़ जाता है और उसकी गति मंद पड़ जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे थर्मल इन्वर्जन या वायुमंडलीय व्युत्क्रमण कहते हैं, जिसमें गर्म हवा की ऊपरी परत ठंडी और भारी हवा को नीचे धरातल के पास ही दबाकर रख लेती है। इस प्राकृतिक जाल में जब उद्योगों, वाहनों, धूल और पराली का धुआं आकर मिलता है, तो यह संपूर्ण बेल्ट एक विशालकाय गैस चैंबर का रूप धारण कर लेती है। जब संकट का क्षेत्र संपूर्ण उत्तर भारत है, तो

केंचुआ को क्लीन चिट मिलेगी या फंस जाएगा पेच?

- राकेश अवतल

केंचुआ यानी चुनाव आयोग की ओर से हलफनामा आ गया है! आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ-साफ कह दिया है कि एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े तीनों बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अकेले फैसले नहीं किए। बाकी दोनों चुनाव आयुक्त भी इन फैसलों में शामिल थे। अब सवाल है कि क्या चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे से विपक्ष की बोलती बंद कर दी है? क्या ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिले जाएगी? और क्या एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली से पहले ही विपक्ष की मुहिम को झटका लग जाएगा? आइए, इस पूरे मामले को पड़ताल करते हैं। सबसे पहले समझिए कि चुनाव आयोग ने कहा क्या है। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के एसआईआर संबंधी आदेश आयोग के सर्वसम्मति फैसले थे। आयोग ने यह भी कहा कि किसी फाइल पर किसी आयुक्त की टिप्पणी, सवाल या सुझाव अपने आप में आयोग का अंतिम फैसला नहीं होता। आयोग की दलील है कि याचिका एक अखबार की रिपोर्ट पर आधारित है और याचिकाकर्ता ने आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की। इसलिए आयोग इसे सुनवाई योग्य नहीं मानता। लेकिन कहानी में एक दूसरा पहलू भी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एसआईआर से जुड़े 14 अहम फैसलों के मामले में दोनों चुनाव आयुक्तों, सुखबीर आ सिंह संधू और विवेक जोशी, ने आपत्तियां



दर्ज की थीं। चुनाव आयोग ने अब अपने हलफनामे में इन आरोपों को खारिज किया है। आयोग ने यह भी स्वीकार किया है कि जुलाई 2026 में आंतरिक कार्य-विभाजन के एक आदेश को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे थे। आयोग के मुताबिक, बाद में दोनों आयुक्तों के संयुक्त निर्देश के कारण वह आदेश लागू नहीं हुआ। यानी मामला इतना सीधा भी नहीं है कि एक हलफनामा आया और सारे सवाल खत्म हो गए। अब आता है फॉर्म नंबर छह का सवाल।नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव किए जाने को लेकर भी विवाद उठा था। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने वैधानिक फॉर्म में संशोधन नहीं किया। ऑनलाइन आवेदन के साथ जो अलग घोषणा-पत्र दिखाया गया था, उसका मकसद आवेदकों को पुरानी मतदाता सूचियों से जोड़ने में मदद करना था। आयोग ने यह भी माना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसे जिस तरह दिखाया गया, उससे बदलाव किए जाने का भ्रम पैदा हो सकता था। अब सवाल यह है कि अगर प्रक्रिया इतनी स्पष्ट थी, तो भ्रम पैदा ही क्यों हुआ? मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है। उसमें नाम जुड़ने, कटने या किसी मतदाता से अतिरिक्त

जानकारी मांगे जाने का मामला महज तकनीकी नहीं है। यह नागरिक के मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष को भी अब सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा। अगर विपक्षी दलों का दावा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों सहयोगी आयुक्तों की सहमति के बिना फैसले किए, तो उन्हें अदालत के सामने ठोस दस्तावेज, फाइलों की टिप्पणियां और दूसरी प्रासंगिक सामग्री रखनी होगी। वहीं चुनाव आयोग को भी अपनी निर्णय प्रक्रिया और दावों की विश्वसनीयता अदालत के सामने स्पष्ट करनी होगी। ध्यान रहे, हलफनामा चुनाव आयोग का पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। अदालत ने अभी इन आरोपों पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इन याचिकाओं पर 27 अक्टूबर को सुनवाई हुई और फिर 10 दिन आगे बढ़ गयी ताकि याचिकाकर्ता हलफनामे पर अपना पक्ष रख सकें। और अगर इस कानूनी लड़ाई का राजनीतिक मतलब समझिए। एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की प्रस्तावित रैली का राजनीतिक महत्व इसी वजह से बढ़ जाता है। विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता, एसआईआर की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को जनता के बीच उठाना चाहता है लेकिन अगर विपक्ष अदालत में अपने आरोपों को मजबूती से साबित नहीं कर पाता, तो उसे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ, यदि अदालत को निर्णय प्रक्रिया में गंभीर खामियां मिलती हैं, तो चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ सकता है। सवाल सीधा है।क्या लोकतंत्र में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता केवल उसके अपने बयान से तय हो जाएगी? या फिर उसे अपने फैसलों की पारदर्शिता और निष्पक्षता से जनता का भरोसा जीतना होगा?

केरल की वृद्ध संरक्षण पहल से जगोगी नई चेतना

- ललित गर्ग

भारत की संस्कृति में माता-पिता को देवतुल्य माना गया है। यहाँ कहा गया है- ‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव’। जिस देश में माता-पिता के चरणों में स्वर्ग देखने की परंपरा रही हो, उसी देश में यदि वृद्धावस्था में माता-पिता अपने ही घर में उपेक्षा, अपमान, अकेलेपन और असुरक्षा का दर्श झेलने के लिए बचते हों, तो यह केवल पारिवारिक विघटन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के सामने खड़ा एक गंभीर प्रश्न है। जिस बुजुर्ग ने अपनी संतान के भविष्य के लिए वर्तमान को खपा दिया, यदि उसी संतान के पास उसके बुढ़ापे के लिए समय, संवेदना और स्नेह न बचे, तो विकास की चमक के बीच मानवीय मूल्यों का अंधेरा साफ दिखाई देता है। ऐसे समय में केरल विधानसभा द्वारा अक्टूबर 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण से संबंधित व्यापक विधेयक पारित किया जाना एक आशाजनक पहल है। यह कानून की किताब में जुड़ा एक नया अध्याय भर नहीं, बल्कि बुजुर्गों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और भरोसा का नया सूर्योदय बनने की क्षमता रखता है। भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों की संख्या लगभग 15 करोड़ बताई जा रही है। अनुमान है कि यह आबादी 2036 तक लगभग 23 करोड़ और 2050 तक 34 करोड़ से अधिक हो सकती है। यह बदलती जनसांख्यिकी हमें चेतावनी भी देती है और अवसर भी। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने मनुष्य की आयु बढ़ाई है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमने जीवन की बढ़ती अवधि को गरिमापूर्ण बनाने की तैयारी भी की है? सिर्फ लंबी उम्र उपलब्धि नहीं है, उस उम्र में सम्मान, आत्मनिर्भरता और अपनापन बनाए



रखना ही वास्तविक उपलब्धि है। केरल की इस पहल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यह बुजुर्गों की समस्याओं को केवल परिवार की निजी जिम्मेदारी मानकर छोड़ देने के बजाय सामाजिक और संस्थागत दायित्व के रूप में देखती है। विधेयक में वरिष्ठ नागरिकों के साथ शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार, क्रूरता और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें बेसहारा छोड़ने जैसे कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ संरक्षण इकाइयों, देखभाल केंद्रों के नियमन, देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण और शिकायतों के निवारण जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। साइबर धोखाधड़ी से बचाव तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों के अधिकार जैसे विषयों को स्थान देना भी बदलते समय की आवश्यकता है। इस पहल का मूल संदेश स्पष्ट है-बुजुर्गों की सेवा सद्भावना का विषय अवश्य है, लेकिन उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना सामाजिक व्यवस्था का अनिवार्य दायित्व भी है। इस विधेयक की सबसे संवेदनशील

अवधारणा है-‘एजिंग इन प्लेस’, अर्थात बुजुर्गों को यथासंभव उनके अपने घर और परिचित परिवेश में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना। वृद्धाश्रमों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन माता-पिता के लिए घर का एक कमरा भी तब अधिक मूल्यवान होता है, जब उसमें अपनत्व की गरमाहट हो। बुजुर्गों को केवल भोजन, दवा और बिस्तर नहीं चाहिए, उन्हें बातचीत करने वाला साथी, उनकी बात सुनने वाला कान, उनके अनुभवों को समझने वाला मन

और उनके अस्तित्व को स्वीकार करने वाला परिवार चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पर कई बार आर्थिक अभाव से अधिक भावनात्मक अभाव पीड़ा देता है। जिस घर में बुजुर्गों की आवाज अनसुनी हो जाती है, वहाँ दीवारें तो रहती हैं, लेकिन परिवार की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। आज संयुक्त परिवारों का विघटन, महानगरों की भागदौड़, विदेशों की ओर पलायन और बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति ने बुजुर्गों के जीवन को कठिन बनाया है। कभी दादा-दादी और नाना-नानी परिवार की जीवंत पाख़ाला होते थे, उनकी कहानियों में इतिहास, अनुभवों में विवेक और आशीर्वाद में जीवन की पूँजी मिलती थी। आज उसी अनुभव-संपदा को कई बार अनुपयोगी समझ लिया जाता है। संपत्ति के लिए माता-पिता पर दबाव डालना, उनकी जमा-पूँजी पर अनुचित अधिकार जमाना, बीमारी में उन्हें अकेला छोड़ देना अथवा उनकी भावनाओं को उस पहुँचाना सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। यह कैसी विडंबना है कि जिन हाथों ने बच्चों को चलना सिखाया, उन्हीं

इसका समाधान किसी एक नगर निगम या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हो ही नहीं सकता। इसके लिए संपूर्ण एयरशेड पर आधारित एक एकीकृत और समेकित क्षेत्रीय रणनीति की आवश्यकता है। वार्षिक वायुमंडलीय संकट का एक प्रमुख और विवादास्पद जैविक कारक कृषि अवशेषों यानी पराली का दहन है। पराली दहन से होने वाला उत्सर्जन उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सवारी करता हुआ पूरे उत्तर भारत के आसमान को अपने आगोश में ले लेता है। चूँकि पराली संकट कृषि अर्थशास्त्र, ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक बहुआयामी मुद्दा है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार का सीधा, आर्थिक और नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य है। इसके लिए फसल विविधीकरण से लेकर उचित प्रौद्योगिकियों के लिए भारी सब्सिडी और बायो-मेथेनेशन प्लांट्स जैसा स्थायी बुनियादी ढांचा समय की आवश्यकता है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि प्रदूषण में केवल पराली का योगदान नहीं है। प्रदूषण की समस्या से प्रस्त दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की सरकारों के बीच आवश्यक तालमेल का अभाव भी स्थितियों को बिगाड़ता है। संकट की दस्तक और उसके गहराते ही राजनीतिक दलों और विभिन्न राज्य सरकारों दोषारोपण का खेल शुरू कर देती हैं। जबकि वायु प्रदूषण जैसी राष्ट्रीय आपदा पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर साझा राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देना आज की सबसे बड़ी मांग है। इस दिशा में प्रदूषण रीढ़ी उपाय करने वाली संस्थाएं केवल कागजी दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें एक सशक्त, स्वायत्त और कठोर निर्णय लेने वाले नियामक के रूप में धरातल पर उतरना होगा।

राष्ट्र निर्माण में नई पीढ़ी की भूमिका

दिनेश प्रसाद

जेन जी और जेन अल्फा की पीढ़ी को समझे समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, अपितु यह है कि वे सीख कहाँ से रहे हैं? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तक से नहीं सीखता। वह अपने आसपास के व्यवहार से भी सीखता है, परिवार से सीखता है, मित्रों से सीखता है, शिक्षक से सीखता है और आज पहले से कहीं अधिक डिजिटल दुनिया से सीखता है। वह जो देखता है, सुनता है और अनुभव करता है, धीरे-धीरे उसके विचार और भावनाओं को आकार देता है। ऐसे में शिक्षा की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक गंभीर एवं बढ़ जाती है। गत दिनों में यह देखने में आया है कि आज की पीढ़ी अधिकारों की चर्चा बहुत करती है, अधिकारों के बारे में जागरूक करना आवश्यक भी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें शिक्षा का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है और समान अवसर पाने का अधिकार है। लेकिन क्या हम उन्हें उतनी ही गंभीरता से उनके कर्तव्यों के बारे में भी बता रहे हैं? या वर्तमान पीढ़ी को उनके कर्तव्यों का ज्ञान है? अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र केवल अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। वह अधिकार और कर्तव्य के संतुलन पर चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए आज की पीढ़ी को यह सिखाना आवश्यक है कि उसे क्या मिलना चाहिए, इसके साथ यह भी समझना होगा कि समाज और राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। विद्यार्थियों को यदि केवल यह बताया जाए कि उनके अधिकार क्या हैं, लेकिन यह न बताया जाए कि दूसरों के भी अधिकार हैं और उन अधिकारों का सम्मान करना उनका कर्तव्य है, तो अधिकार की चेतना अधूरी रह जाएगी। अपने विचार रखने का अधिकार है तो दूसरों के विचार को सुनने का दायित्व भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसके जिम्मेदारी भी है। आज इंटरनेट मीडिया ने इस संतुलन को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। एक क्लिक में कोई सूचना हजारों लोगों तक पहुँच सकती है। ऐसे में आज के विद्यार्थी को यह भी सिखाना होगा कि हर सूचना सत्य नहीं होती, हर वायरल सामग्री साझा करने योग्य नहीं होती और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। यही वह स्थान है जहाँ संस्कार और मूल्य शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनते हैं। संस्कार का अर्थ केवल परंपराओं का पालन करना नहीं है। संस्कार का अर्थ है- सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता, दूसरों के प्रति सम्मान, अनुशासन, संवेदनशीलता, सहानुभूति, सत्य के प्रति आग्रह और अपने कर्तव्यों के प्रति संकल्प। मूल्य व्यक्ति को यह तय करने में सहायता करते हैं कि किसी परिस्थिति में उसके लिए सही आचरण क्या होना चाहिए। जब अधिकारों के साथ संस्कार और कर्तव्य जुड़ते हैं तो अधिकार केवल व्यक्तिगत लाभ का माध्यम नहीं रहता, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण की शक्ति बन जाता है।

हाथों को बुढ़ापे में सहारे के लिए तरसना पड़े। केरल का विधेयक इस समस्या के समाधान की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें बेसहारा छोड़ने पर तीन वर्ष तक के कारावास तथा 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। देखभाल केंद्रों के पंजीकरण, देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण, शिकायतों के निवारण और साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएँ भी प्रस्तावित हैं। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सा संबंधी पूर्वनिर्धारित निर्णयों, कानूनी सहायता और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच को महत्व दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा ने यह विधेयक 26 अक्टूबर 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है, इसे कानूनी के रूप में लागू होने के लिए राज्यपाल की प्रतिक्रिया पूरी करनी होगी।

इस पहल का एक दूरदर्शी पक्ष ‘सिल्वर इकोनॉमी’ की अवधारणा भी है। बुजुर्गों को केवल सहायता प्राप्त करने बल्कि नागरिकों के रूप में न देखें, बल्कि समाज के सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में नहों जाना चाहिए। उनके अनुभव, ज्ञान, कौशल और जीवन-दृष्टि का उपयोग शिक्षा, परामर्श, सामाजिक सेवा, उद्यमिता और सामुदायिक विकास में किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति का अर्थ प्रतिभा की समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन की दूसरी पारी का आरंभ भी हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज उन्हें बौद्ध नहीं, अपनी उम्रक्यू पूँजी माने। पेड़ जग पुराना होता है, तब भी उसकी छाया कम मूल्यवान नहीं हो जाती। इसी तरह अनुभव की परिपक्वता किसी भी राष्ट्र की विकास-यात्रा को दिशा दे सकती है। अब समय है कि केंद्र सरकार के साथ दूसरे राज्य भी केरल की इस पहल से प्रेरणा लें। केंद्र के माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हो तथा आवश्यकतानुसार उसे और सशक्त बनाया जाए।

संक्षिप्त समाचार

समपार संख्या-361 (परसदा फाटक) पर रोड ओवरब्रिज निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि



बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवं सुविधा बढ़ाने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अत्यधिक सड़क यातायात वाले मार्गों पर ट्रेनों के आवागमन के दौरान होने वाली असुविधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न समपार फ़टकों पर रोड ओवरब्रिज रोड अंडरब्रिज एवं लिमिटेड हाइट सबवे (सास) का निर्माण किया जा रहा है, ताकि यातायात को सुरक्षित रूप से वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया जा सके। इसी क्रम में मंडल के जयरामनगरड्ड्गतौरा स्टेशनों के मध्य किमी 706/21-33 पर स्थित समपार संख्या 361 (परसदा फटक) पर रोड ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस रोड ओवरब्रिज निर्माण कार्य की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए 36-36 मीटर लंबे चार कंपोजिट गर्डरों की सफल लॉन्चिंग पूरी कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। यह महत्वपूर्ण कार्य गति शक्ति इकाई के इंजीनियरों की देखरेख में सुनियोजित कार्ययोजना, तकनीकी दक्षता और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ पूरा किया गया। गर्डर लॉन्चिंग के लिए 500 टन क्षमता वाली क्रेनों का उपयोग किया गया। संपूर्ण लॉन्चिंग कार्य दो ट्रेफ़िक ब्लॉक में, प्रत्येक 1 घंटे 30 मिनट की अवधि में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। गर्डरों की सफल लॉचिंग के साथ ही इस रोड ओवर ब्रिज निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। एप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एप्रोच रोड निर्माण पूर्ण होते ही परसदा फटक के साथ पूरा किया गया। सड़क उपयोगकर्ताओं एवं वाहनों को सुरक्षित, संरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल यात्रियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा-आपत्ति आमंत्रित

बिलासपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। बैंक की स्टाफउप समिति की 6 अक्टूबर 2026 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत दो आवेदकों की सूची जारी कर आम जनता एवं संबंधित पक्षों से दावा-आपत्ति मंगाई गई है। बैंक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी सूची में स्वर्गीय प्रजेश सिंह चंदेल की पत्नी श्रीमती रंजिता सिंह, निवासी कोसा, तहसील पामगढ, जिला जांजगीर-चांपा तथा स्वर्गीय जितेंद्र पाण्डेय के पुत्र श्री विवेक पाण्डेय, निवासी जोरापारा, सरकंडा, बाल्टी फेक्ट्री के पीछे जिला-बिलासपुर के नाम शामिल हैं। दोनों आवेदकों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत इनके प्रकरणों पर सहमति के आधार पर विचार किया गया है। बैंक प्रबंधन ने बताया कि संबंधित आवेदकों अथवा उनके आश्रित परिवार के किसी सदस्य के संबंध में कोई आपराधिक या न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में कार्यरत होने अथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति की जानकारी होने पर सात दिनों के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। दावा-आपत्ति बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जिले में स्थित बैंक के नोडल कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। कार्यालय में पत्र व्यवहार हेतु ई-मेल आईडी अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नेहरू चौक बिलासपुर पिन कोड 495001 में जानकारी प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त दावा-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण करने के बाद अनुकंपा नियुक्ति की आगामी कार्रवाई की जाएगी।

स्पेशल कैंपेन 6 के अंतर्गत एसईसीएल ने निर्धारित लक्ष्यों को किया पार,स्क्रैप निपटान से अर्जित किए 26.17 करोड़ रुपए...

■ 226 स्थलों पर 47 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में स्वच्छता कार्य, 4,602 मीट्रिक टन स्क्रैप का निपटान

बिलासपुर। साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने स्पेशल कैंपेन 6 के अंतर्गत स्वच्छता, स्क्रैप निपटान, स्थान के बेहतर उपयोग एवं रिकॉर्ड प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज करते हुए कई निर्धारित लक्ष्यों को समय से पहले पार कर लिया है। एसईसीएल ने निर्धारित 225 स्थलों के लक्ष्य के मुकाबले 226 स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियाँ संचालित की हैं। इस दौरान 40 लाख वर्गफुट के लक्ष्य के विरुद्ध 47 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में स्वच्छता कार्य किया गया है। अभियान के अंतर्गत

एसईसीएल ने 3,300 मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 4,602 मीट्रिक टन स्क्रैप का निपटान कर लगभग ₹26.17 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। यह उपलब्धि संसाधनों के बेहतर उपयोग, व्यवस्थित स्क्रैप निपटान एवं कार्यस्थलों के प्रभावी प्रबंधन की दिशा में कंपनी के प्रयासों को दर्शाती है। रिकॉर्ड प्रबंधन एवं लंबित प्रकरणों के निपटान में उल्लेखनीय प्रगति- स्पेशल कैंपेन 6 के अंतर्गत एसईसीएल ने भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक फ़इलों के प्रबंधन में भी निर्धारित लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने 500 भौतिक फ़इलों की समीक्षा के लक्ष्य के विरुद्ध 2,100 फ़इलों की समीक्षा की है, जबकि 200 के लक्ष्य के मुकाबले 872 भौतिक फ़इलों की नियमानुसार छंटनी कर उन्हें रिकॉर्ड से हटाया गया है। इसी प्रकार, 7,000 ई-फ़इलों की समीक्षा के लक्ष्य के विरुद्ध 14,215 ई-फ़इलों की समीक्षा की



गई है। वहीं 3,000 ई-फ़इलों को बंद करने के लक्ष्य के मुकाबले 13,708 ई-फ़इलों का निस्तारण किया गया है। इन प्रयासों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित बनाने, लंबित मामलों के निपटान एवं सुशासन को बढ़ावा देने में सहायता मिल रही है। ई-वेस्ट प्रबंधन एवं 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल- स्पेशल कैंपेन 6 में



ई-वेस्ट के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण एवं निपटान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत एसईसीएल मुख्यालय सहित विभिन्न संचालन क्षेत्रों में ई-वेस्ट संग्रहण अभियान चलाए जा रहे हैं। एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर में कर्मचारियों द्वारा पुराने एवं अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जमा करने के लिए विशेष ई-वेस्ट

■ बिलासपुर के माटी पुत्र संयुक्त संचालक रहे राकेश जयसवाल, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक का नगर विधायक ने किया सम्मान

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हमर बिलासपुर सोशल मीडिया रूप द्वारा संचालित 'स्वच्छ बिलासपुर, आपकी बात' पहल में स्वच्छता को लेकर उत्कृष्ट सुझाव एवं विचार प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को भी रूप के मुख्य संरक्षक श्री अमर अग्रवाल ने सम्मानित किया। मालूम हो जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की प्रेरणा से शहर के हमर बिलासपुरसोशल मीडिया रूप में 24 अक्टूबर तक स्वच्छ बिलासपुर आपकी बात विषय पर सदस्यों से सुझाव और

आइडिया आमंत्रित किए गए थे,जिसमें 33 आइडिया अंतिम चरण में निर्णय समिति को प्रेषित किए गए जिसमे से प्रथम पांच सर्वश्रेष्ठ आइडिया व्यक्त करने वाले सदस्यजन को पुरस्कृत किया गया। निर्णायक समिति में श्री राजीव लोचन तिवारी, श्री राधाकिशन शर्मा, विकास चौबे जी रंिकू मित्रा, रौनक साव शामिल थे। उन्होंने कहां मॉडल टेक्नोलॉजी के नवीन दौर में सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग करना चाहिए सर्वश्रेष्ठ आइडिया देने वाले विजेताओं में श्री आशीष वाजपेयी (टिकरापारा), श्री मोनू रजक (अधिवक्ता), श्रीमती दीपाली दुआ (इनर व्हील क्लब), श्री रजनीश ताम्रकार (व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता) तथा श्री विजेंद्र तिवारी (अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता) शामिल रहे। सभी को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की प्रेरणा से शहर के



सोशल मीडिया रूप में 24 अक्टूबर तक 'स्वच्छ बिलासपुर, आपकी बात' विषय पर नागरिकों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए गए थे। इस पहल के अंतर्गत प्राप्त सुझावों में से 33 विचार अंतिम चरण के लिए निर्णायक समिति के समक्ष रखे गए, जिनमें पांच सर्वश्रेष्ठ

सुझावों का चयन कर उनके प्रस्तुतकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। निर्णायक समिति में श्री राजीव लोचन तिवारी, श्री राधाकिशन शर्मा, श्री विकास चौबे, रौनक साव शामिल थे। राजेंद्र नगर स्थित विधायक निवास पर हमर बिलासपुर रूप के वरिष्ठ सदस्य एवं सेवानिवृत्त संयुक्त

संचालक नगरीय प्रशासन श्री राकेश जायसवाल तथा पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कौशिक को भी उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के लिए शाल, श्रीफ़त्त एवं स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। श्री अमर अग्रवाल ने श्री राकेश जायसवाल को कार्यशैली और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक सजग और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वहीं श्री अजय कौशिक ने अपने संपूर्ण सेवाकाल में शिक्षा व्यवस्था के सुधार और विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं। दोनों अधिकारियों की सेवाएं और अनुभव शहर के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने दोनों को सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वस्थ एवं सुखद जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

बलराम पांडे को मिली डॉक्टरेट की उपाधि

बिलासपुर। रतनपुर लेखक एवं इतिहासकार बलराम पांडे को थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार के हरिद्वार में संपन्न दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में थावे विद्यापीठ के कुलाधिपति श्री श्री 1008 श्री परम पूज्य हरिहरानंद जी महाराज व कुलपति डॉ विनय पाठक के कर कमलों उनकी यह सम्मान प्रदान किया गया डॉक्टर गजेंद्र तिवारी के मार्गदर्शन में प्राचीन राजधानी रतनपुर, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, स्थापत्य एवं लोक जीवन का बहु आयामी अध्ययन के 203 पेज के शोध ग्रंथ के आधार पर उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई ज्ञात हो कि विगत 34 वर्षों से रतनपुर के इतिहास ,पर्यावरण एवं पुरातत्व पर आ पने लगातार कार्य किया है रतनपुर के लगभग सभी मंदिरों का आलेख विभिन्न समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होता रहा है पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए चतुर यू गी नगरी रतनपुर धाम व छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर नामक



पुस्तिका आपने लिखी है वही रतनपुरिहा गम्मत को पुनर्जीवित करने तथा छठी व हरदिया ही को जो रतनपुर की प्राचीन संस्कृति है के ऊपर भी अपने कार्य किया है रतनपुरिहा गम्मत जो कि लगभग वित्नुति के कगार पर पहुंच चुका था जिसे आपने महामार्ड पारा में विगत 34 वर्षों तक संपन्न कराया डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए जाने पर नगर के साहित्यकारों व प्रबुद्ध जनों डॉक्टर दिनेश पांडे, डॉक्टर सुखदेव कश्यप, अनिल अग्रवाल, महंत दिव्यकांत, अश्वनी दुबे, संतोष शर्मा,

ओमप्रकाश दुबे ,राजेंद्र मिश्रा, राजेंद्र दुबे ,राजेश शर्मा, रविंद्र दुबे ,रमन शर्मा, शिवानंद पांडे ,विकल जायसवाल, रूपचंद्र तंबोली, लक्ष्मी पांडे, रश्मि शर्मा, प्रीति शर्मा, चंद्रकांत शर्मा नीलू पांडे, वंदनी मिश्रा ,ओमप्रकाश कश्यप, गेंदराम कौशिक, होरीलाल गुप्ता, भरत लाल गुप्ता, किशनलाल तंबोली, शंकर लाल पटेल, के आर कौशिक, सहित नगर के गहमाय्य नागरिकों ने खुशी व्यक्त की है तथा उन्हें प्राप्त इस उपाधि को उन्होंने रतनपुर इतिहास के प्रति की गई सेवा का फल बताया है।

बकावंड जनपद पंचायत में विकास टप, समीक्षा बैठकें बंद

93 ग्राम पंचायतों के विकास पर उठे सवाल, जनपद सदस्य लालेंद्र बाकडे ने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर साधा निशाना



सदस्यों के बीच तालमेल नहीं है, तो क्षेत्र के विकास कार्यों को गति कैसे मिलेगी?

उन्होंने बताया कि बकावंड जनपद पंचायत में कुल 25 जनपद सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में सड़क, पेयजल, आवास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं। लेकिन नियमित बैठकें नहीं होने से जनप्रतिनिधियों को अपनी

समस्याएं और क्षेत्र की मांगें अधिकारियों के सामने रखने का उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है।

जनपद सदस्य ने जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) से मांग की है कि नियमानुसार प्रत्येक दो माह में सामान्य सभा की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। बैठक में शासन की योजनाओं, विकास कार्यों और लंबित समस्याओं की समीक्षा हो, ताकि सभी जनपद सदस्यों को योजनाओं की जानकारी मिले और उसका लाभ आम जनता तक पहुंच सके।

बाकडे ने तंज करते हुए कहा कि यदि जनपद पंचायत में इसी तरह बैठकें और विकास कार्य प्रभावित होते रहे, तो आने वाले समय में विकास के नाम पर केवल दो समोसा और एक कप चाय ही रह जाएगा ?। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत केवल औपचारिकता निभाने का मंच नहीं ब्लेक 93 ग्राम पंचायतों के विकास की महत्वपूर्ण स्वस्थ है। यहां नियमित बैठकें और जवाबदेही सुनिश्चित होना जरूरी है।

विशेष अभियान 6.0 के तहत जिले की संस्थाओं में चला स्वच्छता अभियान.....

बिलासपुर। भारत सरकार के

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार विशेष अभियान 6.0 के तहत आज जिले की 1955 संस्थाओं में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों सहित विभिन्न विभागीय संस्थाओं में साफ-सफ़ाई, पौधरोपण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान में महिलाओं, बालिकाओं, स्व-सहायता समूहों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न वर्गों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। अभियान के तहत सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सशक्तिकरण केंद्र, हब, पालन केंद्र, शक्ति सदन एवं सखी निवास सहित अन्य संस्थाओं में



विशेष साफ-सफ़ाई की गई। कार्यालयों में रिकॉर्ड एवं अभिलेखों को व्यवस्थित करने के साथ ही अनुपयोगी सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर एवं पंपलेट वितरित किए गए तथा पौधरोपण भी किया गया। अभियान में शासकीय प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की

सक्रिय सहभागिता रही। विशेष अभियान के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की हेल्पलाइन 1515, पोषण ट्रैकर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा सीपीग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए ई-चौपाल के माध्यम से कार्रवाई की गई। अभियान के अंतर्गत आयोजित सभी स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी निशान शक्ति डैशबोर्ड पर दर्ज की गई।

तूफान से फसल क्षति का युद्ध स्तर पर होगा सर्वे, किसानों को दिलाई जाएगी राहत



■ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कलेक्टर ने ली आकस्मिक बैठक, सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश

■ गैर-बीमिट किसानों को आरबीसी 6-4 के तहत मिलेगी सहायता, राजस्व विभाग करेगा नुकसान का सर्वे

उनकी फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें भी राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के तहत पात्रतानुसार सहायता दी जाएगी। उन्होंने राजस्व विभाग को ऐसे किसानों की फसल क्षति का सर्वे कर नियमानुसार सहायता के प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाकर अगले कुछ दिनों में सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल क्रीप सर्वे (डीसीएस) का अनुभव रखने वाले युवाओं को भी सर्वे की जिम्मेदारी सौंपने को कहा, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन शीघ्र किया जा सके। जिले में एचडीएफसी एग्री कंपनी के माध्यम से चालू खरीफ मौसम में लगभग 47 हजार किसानों ने फसल बीमा कराया है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि विपत्ति की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कठिन परिस्थितियों में मेहनत कर अन्न उपजाने वाले किसानों का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। उनकी फसलों को हुई वास्तविक क्षति के लिए नियमानुसार राहत सहायता और बीमा दावे का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने कृषि एवं राजस्व विभाग को किसानों के नियमानुसार के मुआवजा एवं फसल बीमा दावे का लाभ दिलाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं कराया है और

बिलासपुर। मुख्यमंत्री

विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में बारिश और तूफ़ान से फसलों को हुए नुकसान का त्वरित सर्वे कर प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनी के अधिकारियों की अपने कक्ष में आकस्मिक बैठक लेकर युद्ध स्तर पर सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की बारिश और तूफ़ान से धान सहित अन्य फसलों को हुई वास्तविक क्षति का आकलन कर किसानों को नियमानुसार मुआवजा एवं फसल बीमा दावे का लाभ दिलाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं कराया है और



ओटीटी के आने से कलाकारों को मिल रहे बेहतर मौके

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी फिल्म 'गजब रात' को लेकर चर्चा में हैं। यह शुक्रवार, 23 अक्टूबर को रिलीज हो गई है। इसमें उनके साथ दिव्या दत्ता और श्रद्धा दास भी हैं। यह वही फिल्मों है, जो इसी साल फरवरी में अपने टाइटल 'घूसखोर पंडित' को लेकर विवादों में रही थी। अब नए नाम के साथ फिल्म आई है। इस बीच मनोज बाजपेयी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों को एक ही तरह के किरदारों तक सीमित रखने की सोच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ने कई टैलेंटेड एक्टरों को सही मौके न देकर उनका टैलेंट बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्री के 'बुरे कर्म' हैं, जो एक्टरों को तबाह कर देती है। खुद अपने बारे में उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिभा का 25 प्रतिशत हिस्सा ही अब तक इस्तेमाल हुआ है। 'सत्या' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले मनोज बाजपेयी ने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन कलाकारों को एक ही तरह के किरदारों में बांधकर उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने इंडस्ट्री के 'बुरे कर्मों' का जिक्र करते हुए कहा, 'इस इंडस्ट्री में कई कलाकारों को स्टीरियोटाइप किया जाता है, और ऐसा करके हमने कई बेहतरीन टैलेंट को बर्बाद कर

दिया है। मैंने हमेशा कहा है कि इस इंडस्ट्री की बदनामी है और इसके सिर पर ऐसे महान कलाकारों को बर्बाद करने का बुरा कर्म है। सेट पर उन्हें कोई अहमियत न देकर, उनके किरदारों को सीमित करके और उनके साथ खराब बर्ताव करके उन्हें खत्म कर दिया गया। कई लोग तो बिना किसी पहचान के ही गुमनामी में खो गए।'

मनोज बाजपेयी का मानना है कि फिल्म निर्माता अब तक उनकी अभिनय क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अपनी प्रतिभा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा यही माना है कि मेरी अभिनय क्षमता का केवल 25 प्रतिशत ही इस्तेमाल हुआ है; अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक कलाकार का लालच या उसकी भ्रूख है, और मुझे खुशी है कि मेरे अंदर अभी भी कुछ कर दिखाने की वह आग बाकी है।' मनोज के मुताबिक, एक कलाकार के अंदर हमेशा कुछ नया करने की चाह होती है। उन्हें खुशी है कि इतने लंबे करियर के बाद भी उनके अंदर बेहतर काम करने और नए किरदार निभाने का जुनून बना हुआ है। मनोज बाजपेयी ने माना कि उन्होंने भी अपने करियर में इस तरह की सोच का सामना किया है और इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना

पड़ा। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह बैवैनी पूरी तरह से समझ में आती है, क्योंकि हम आज भी काफी हद तक औपनिवेशिक मानसिकता से घिरे हैं और पदानुक्रम में बहुत विश्वास करते हैं। वह मुख्य अभिनेता है, वह मुख्य अभिनेत्री है, यह एक कैरेक्टर एक्टर है, यह एक सपोर्टिंग एक्टर है, इन्हीं आधारों पर हम एक पदानुक्रम तय कर देते हैं। मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ और मैंने व्यक्तिगत स्तर पर कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि जैसा कि दिव्या ने बिल्कुल सही कहा अब ऐसा नहीं है।' मनोज बाजपेयी का मानना है कि ओटीटी

प्लेटफॉर्मों के आने से फिल्म इंडस्ट्री में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। अब छोटे या सहायक किरदार निभाने वाले कलाकारों को भी अपना टैलेंट दिखाने के ज्यादा मौके मिल रहे हैं। मनोज ने कहा, 'पहले, छोटे या सपोर्टिंग रोल करने वाले कई एक्टरों के साथ काफी नाइंसाफी होती थी, लेकिन अब हालात काफी बेहतर हैं। कई प्रड्यूसर्स अब इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि सभी को एक जैसा सम्मान और मौके मिलें। खासकर ओटीटी के आने के बाद से चीजें पूरी तरह बदल गई हैं। हमें अपने देश में ओटीटी के आने का शुक्रगुजार होना चाहिए।'

दर्शक अब कहानियाँ और किरदारों को बारीकी से समझते हैं

ओटीटी के प्रभाव पर बात करते हुए मनोज ने कहा, 'आज परिवार साथ बैठकर कंटेंट देख रहे हैं। वे बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं और उन पर विस्तार से बात करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं किसी डीपम (डिस्ट्रिब्यूट मजिस्ट्रेट) या उनके परिवार के साथ बैठता हूँ, तो वे जिस तरह से किसी किरदार और कहानी की बारीकियों पर चर्चा करते हैं, वह वाकई हैरान कर देने वाला होता है। उन्हें बिल्कुल पता होता है कि कहा क्या कमी रह गई। किसी भी क्रिटिक की समीक्षा सुनने के बजाय, मुझे इन आम दर्शकों की बातें सुनना कहीं ज्यादा अच्छा लगता है।' मनोज के मुताबिक, आज दर्शक फिल्मों और वेब सीरीज को पहले से ज्यादा ध्यान से देखते हैं। वे कहानियों और किरदारों की बारीकियों को समझते हैं और अपनी राय खुलकर रखते हैं।

डिजिटल क्रिएटर से एक्ट्रेस बनने तक का सफर

दर्शकों का प्यार देता है कॉन्फिडेंस

एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में डिजिटल क्रिएटर से फिल्मों तक के अपने सफर और दर्शकों से मिले प्यार के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े लोगों की वजह से उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है। एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने कहा कि जब वह बड़े कलाकारों के साथ फिल्मों में काम करती हैं, तो उनके मन में यह चिंता नहीं रहती कि दूसरे लोग उन्हें पसंद करेंगे या नहीं। इसके बजाय वह चाहती हैं कि जो दर्शक उनकी फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, उन्हें भी उनका काम पसंद आए। प्राजक्ता ने कहा, 'ज्यादातर जगहों पर मैं थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरी अपनी कम्युनिटी है। मैं यह बात विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि मुझे जो काम मिला है, उसके लिए मैं

बहुत आभारी हूँ। जब मैं 'जुगजुग जिओ' कर रही थी, तब वह मेरी सबसे बड़ी फिल्म थी। उसमें बड़े कलाकार और शानदार स्टारकास्ट थी। लेकिन, मेरे दिमाग में यह नहीं था कि पता नहीं वे लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं।' उन्होंने कहा, 'मेरी सोच यह थी कि जो लोग फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, वे मुझे पसंद करें।' मैं चाहती थी कि दर्शकों को मेरा काम अच्छा लगे, लेकिन इसके लिए दूसरे कलाकारों की अहमियत कम नहीं होनी चाहिए।' प्राजक्ता ने बताया कि 'जुगजुग जिओ' के सेट पर अनिल कपूर, नीतू कपूर, किरारा आडवाणी, करण जोहर, मनीष पॉल और वरुण धवन समेत सभी लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। एक्ट्रेस ने कहा, 'डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों से मिले प्यार ने मुझे फिल्मों में काम करते समय भी आत्मविश्वास दिया। मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं अपने काम से उन लोगों का दिल जीत सकूँ, जो लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मेरे काम को देखते हैं।'

एक्शन ड्रामा फिल्म 'प्रताप' में नजर आएंगी ईशा देओल

ईशा देओल, फिल्म 'प्रताप' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। प्रदीप रंगवानी और यूवी फिल्मस द्वारा प्रस्तुत इस आगामी एक्शन ड्रामा के निर्माताओं ने ईशा देओल को कैरेक्टर पोस्टर जारी किया है, जिसमें वह पूनम के किरदार में नजर आ रही हैं। पूनम की कहानी जीवन में आने वाले अप्रत्याशित मोड़ों, आत्मखोज और मुश्किल हालात में सामने आने वाली अंदरूनी ताकत को दर्शाने का वादा करती है। पूनम के लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया है और उसने अपनी जिंदगी उन रिश्तों और विश्वास के आधार पर बनाई है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन तब क्या होता है, जब जिस सच्चाई पर उसने हमेशा भरोसा किया, वही बिखरने लगती है? ऐसे हालात का सामना करते हुए, जो उसके विश्वास और सोच को चुनौती देते हैं, पूनम को अपने पैरों पर खड़े होकर उस ताकत को पहचानना होगा, जिससे वह अब तक अनजान थी। हालांकि, उसके सफर से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उसका किरदार एक ऐसे भावनात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है, जो उसकी अब तक की पहचान से कहीं आगे जाती है। ईशा देओल का यह कैरेक्टर पोस्टर हाल ही में जारी किए गए फिल्म के मोशन पोस्टर के बाद सामने आया है, जिसमें अमित साध एक जांबाज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के किरदार में नजर आए हैं, जो खुद कानून के दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। सत्ता, न्याय अपने फैसलों के परिणामों की पड़ताल करती 'प्रताप' की कहानी में जहाँ व्यक्तिगत संघर्षों के साथ-साथ हार्ड-स्टेक्स ड्रामा भी देखने को मिलेगा, वहीं, पूनम का सफर फिल्म की कहानी में एक मजबूत भावनात्मक पहलू जोड़ता है। सचिन सराफ के लेखन और निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमित साध और ईशा देओल के अलावा तिम्माशु धूलिया, सीमा बिस्वास और मिलिंद गुणाजी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

05 फरवरी को दस्तक देगी हर्षवर्धन राणे की 'सिला'

नए साल में हर्षवर्धन राणे के नए तेवर देखने को मिलने वाले हैं। हाल ही में उनकी फिल्म 'पुलिस कंपनी' की रिलीज डेट का एलान किया गया था। यह फिल्म अगले साल जून में दस्तक देगी। इस बीच एक और फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है। अभिनेता की

आगामी फिल्मों की लिस्ट में 'सिला' का नाम भी शामिल है। हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सिला' एक्शन-रोमांटिक फिल्म होगी। आज इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें हर्षवर्धन इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। यह अगले साल मोहब्बत वाले महीने यानी फरवरी में रिलीज होगी। पोस्ट के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक, यह फिल्म 05 फरवरी 2027 को रिलीज होने वाली है।

कल्पना से भी परे होगी कहानी

फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने इसकी कहानी को लेकर संकेत दिया है। यह सरसंसे और थ्रिलर से भरपूर एक्शन-रोमांटिक फिल्म होगी। पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा है, 'किस्मत से परे प्यार। हद से परे एक सफर और कल्पना से भी परे एक कहानी।' 'सिला' की तलाश शुरू।

कौन-कौन होगा फिल्म का हिस्सा

बता दें कि फिल्म 'सिला' का निर्देशन उमंग कुमार ने किया है। इसमें 'बिग बॉस 18' के विजेता करण वीर मेहरा भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे फिल्म में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। 'सिला' फिल्म में हर्षवर्धन को विराट नाम के किरदार में देखा जाएगा। वहीं, सादिया खतीब भी फिल्म का हिस्सा है।

करण टैकर ने शुरू की नए प्रोजेक्ट की शूटिंग!

मुंबई एक्टर करण टैकर ने अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग स्कॉटलैंड में शुरू कर दी है और इसकी पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। करण ने शूट के पहले दिन की बिहाइंड द सीन्स तस्वीर पोस्ट करते हुए एक ऐसा नोट लिखा, जिसने उनके नए सफर को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। तस्वीर शेयर करते हुए करण ने लिखा, 'एक नया प्रोजेक्ट, एक नया चैप्टर और एक बड़ा रिस्क। अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़े रिस्क ही सबसे रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं।' अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है।' करण की इस पोस्ट में शूटिंग के शुरुआती दिनों की झलक देखने को मिली। हालांकि, उन्होंने फिलहाल प्रोजेक्ट से जुड़ी डिटेल्स को सीक्रेट ही रखा है, लेकिन उनके कैप्शन से साफ है कि वह इस नई शुरुआत को लेकर काफी एक्साइटेटेड हैं। स्कॉटलैंड में कैमरा रोल हो चुका है और अब फैंस को इंतजार है कि आखिर इस बार करण क्या नया लेकर आने वाले हैं। इस बार करण का लुक भी काफी बदला-बदला नजर आ रहा है। बड़े हुए बाल और घनी दाढ़ी के साथ उनका रफ-टफ अंदाज चर्चा में है। नए प्रोजेक्ट के साथ उनका यह नया लुक भी फैंस की उत्सुकता बढ़ा रहा है। हालांकि, प्रोजेक्ट की कहानी और बाकी कलाकारों को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। वर्कफ्रंट की बात करें तो स्कॉटलैंड में शूटिंग शुरू होने के साथ करण टैकर के पास कई और प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। यानी आने वाला वक्त उनके लिए काफी बिजी और दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल, फैंस को करण के अगले अपडेट का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस नए प्रोजेक्ट के पते अभी पूरी तरह खुले नहीं हैं!

रश्मिका मंदाना ने अपने हिंदी एक्सैंट की आलोचनाओं पर दिया जवाब

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हाल ही में अपने पति और चर्चित एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ करण जोहर के शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' में पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने साउथ इंडियन एक्सैंट को लेकर होने वाली अपनी आलोचनाओं पर बात की। अभिनेत्री ने कहा कि वे ऑनलाइन होने वाली ट्रोलांग को अपनी भाषा या फिल्म इंडस्ट्री चुनने में रूकावट नहीं बनने देंगी। रश्मिका मंदाना ने अपने हिंदी एक्सैंट की आलोचनाओं पर जवाब देते हुए कहा है कि उनसे यह उम्मीद करना गलत है कि वे साउथ इंडियन न लेंगे। वे इस इलाके से आती हैं। अभिनेत्री ने कहा कि वे अपनी डायलॉग डिलीवरी पर टिप्पणियों को अपनी भाषा या फिल्म इंडस्ट्री चुनने में रूकावट नहीं बनने देंगी। रश्मिका ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि साउथ इंडियन एक्सैंट को प्रॉब्लम क्यों माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मुझे इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा साउथ इंडियन एक्सैंट है, लेकिन मैं साउथ इंडिया से हूँ। इसलिए मेरा एक्सैंट तो होगा ही। इसके अलावा कुछ और सोचना गलत है।' अभिनेत्री ने कहा कि अगर कोई डायरेक्टर यह मानता है कि किसी दूसरे आर्टिस्ट की आवाज किसी किरदार पर ज्यादा सूट करेगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि, उनके डायरेक्टर्स ने अब तक यही पखंड किया है कि वह खुद के लिए डब करें।



समान नागरिक संहिता से सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और समान नागरिक अधिकारों को मिलेगी मजबूती

स्वयंप्रभा फ़उंडेशन और आम्रपाली गृह निर्माण संस्था ने समान नागरिक संहिता समिति को सौंपे महत्वपूर्ण सुझाव

आदिवासी परंपराओं के संरक्षण, महिलाओं के समान अधिकार और लिव-इन संबंधों में बच्चों के भविष्य की सुरक्षा पर विशेष जोर

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026/ छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी और जनसंवाद का क्रम जारी है। इसी कड़ी में स्वयंप्रभा फ़उंडेशन एवं आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, रायपुर के प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता

समिति के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों सेवानिवृत्त आईएएस श्री एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना। समिति की ओर से सुझावों के समुचित परीक्षण एवं विचार-विमर्श के दौरान उन्हें संज्ञान में लेने की बात कही गई। प्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यापक जनभागीदारी और विभिन्न समुदायों के विचारों के आधार पर तैयार की जाने वाली समान नागरिक संहिता सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। प्रतिनिधियों ने सुझाव प्रस्तुत किया कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार,



महिलाओं को न्यायपूर्ण संरक्षण और समाज में समानता एवं समरसता को बढ़ावा देना होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति,

परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। स्वयंप्रभा फ़उंडेशन के अध्यक्ष श्री शिव नारायण मुंदड़ा, डॉ.

मुकेश शाह तथा आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित के अध्यक्ष श्री इन्द्रनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति एवं पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कानूनों में समानता स्थापित होने से नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी, इससे कानूनी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी। प्रतिनिधियों ने महिलाओं के अधिकारों को विशेष प्राथमिकता देते हुए कहा कि बहुविवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं, भरण-पोषण संबंधी असमानताओं और संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव को दूर करने की दिशा में प्रभावी प्रावधान किए जाने चाहिए। विशेष रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार तथा महिलाओं को विवाह और तलाक के मामलों में न्यायपूर्ण संरक्षण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय आबादी के

उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों की है। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सदियों पुरानी परंपराएं हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले इनकी परंपराओं, सामाजिक हितों और संवैधानिक संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े सामाजिक एवं कानूनी पहलुओं पर भी सुझाव दिए गए। प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे संबंधों के पंजीयन की उपयुक्त नीति चाहिए। विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही इन संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों के उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट एवं न्यायसंगत प्रावधान आवश्यक हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर ने र्वा वित्तीय इतिहास: ष्टश्वह अपेक्षा व्यास के कार्यकाल में दर्ज हुई अभूतपूर्व प्रगति

रायपुर, 30 अक्टूबर: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर ने अपनी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) श्रीमती अपेक्षा व्यास के कुशल नेतृत्व में वित्तीय सुदृढ़ता, किसान कल्याण और डिजिटल सेवा-विस्तार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हाल ही में श्रीमती व्यास का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (मुख्यालय, नवा रायपुर) में कर दिया गया है। उनके कार्यकाल में बैंक द्वारा हासिल की गई उत्तरोत्तर प्रगति वर्तमान में सहकारिता जगत में सराहना का विषय बनी हुई है।

सकल लाभ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में निरंतर ऐतिहासिक 216-216 करोड़ रुपये का सकल लाभ अर्जित किया है। दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति में बैंक की कार्यशील पूंजी 8,600 करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल जमा अमानतें 6,971 करोड़ रुपये से अधिक



रही, जो बैंक सुदृढ़ता और खाताधारकों के अटूट विश्वास का प्रमाण है।

किसानों को 11,583 करोड़ का समयबद्ध भुगतान- धान खरीदी वर्ष 2025-26 में बैंक की समितियों द्वारा कुल 37,36,666 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इसके अंतर्गत समर्थन मूल्य हेतु 8,854 करोड़ रुपये एवं कृषक उन्नति योजनांतर्गत 2,729 करोड़ रुपये को मिलाकर कुल 11,583 करोड़ रुपये का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त, 30 सितंबर 2026 की स्थिति में बैंक द्वारा 2,200.16 करोड़ रुपये का खरीफ अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किया गया, जो

सुशासन की मिसाल सीएम हेल्यलाइन- जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही डिजिटल पहल

शिकायत से समाधान तक का सफर आसान

धनंजय रावौर संयुक्त संचालक, जनसंपर्क लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें शासन और प्रशासन सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाया गया एक बेहद प्रभावी कदम सीएम हेल्यलाइन 1076 है। आज यह हेल्यलाइन राज्य के आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके माध्यम से घर बैठे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री हेल्यलाइन 1076 और प्रशासनिक कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि हेल्यलाइन का उद्देश्य केवल शिकायतों के आंकड़ों को कम करना या पोर्टल पर उन्हें क्लोज कराना नहीं है, बल्कि नागरिकों को वास्तविक और संतोषजनक समाधान दिलाना है।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश- संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि उनकी अपेक्षा बहुत स्पष्ट है-जनता को अपनी समस्या लेकर भटकना न पड़े। अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके परिश्रम की वे सराहना भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही से पूरे प्रशासन की छवि खराब हो, यह उचित नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा; जहां कमी है, वहां सुधार का अवसर मिलेगा; और जो लगातार लापरवाही करेंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री हेल्यलाइन 1076 का मूल मंत्र संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान होना चाहिए।

विस्तृत कार्यप्रणाली और अब तक के आंकड़े-छत्तीसगढ़ शासन के



टोल-फ्री नंबर 1076 के माध्यम से नागरिक सरकारी सेवाओं और अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह कॉल सेंटर 24 घंटे और सातों दिन चालू रहता है। राज्य शासन के 49 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। सीएम हेल्यलाइन 1076 पर अब तक 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2 लाख 10 हजार 649 शिकायतों का सफल निराकरण किया जा चुका है।

शेष 34 हजार 727 शिकायतों पर तीव्र गति से कार्रवाई जारी है। इस प्रकार, अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 85.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है।

किन विषयों पर की जा सकती है शिकायत?—सीएम हेल्यलाइन 1076 पर आम जनता से जुड़ी समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं—

तरुण बन्धोर- जनता के गोट **धरसींवा:** पंडित श्यामाचरण शुक्ल शासकीय महाविद्यालय में 'युवा संवाद - लोकतंत्र बनाम अराजकता+ विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा ने छत्र-छत्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश का युवा आज केवल भविष्य का निर्माता ही नहीं, बल्कि वर्तमान प्रगति का भी सबसे बड़ा संवाहक है। उन्होंने युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक कर्तव्यों और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों के साथ हुआ। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और इसकी लोकतंत्री हमारी संस्थाओं, कानून के सम्मान व संविधान के प्रति अटूट



निष्ठा पर टिकी है। उन्होंने युवाओं से किसी भी प्रकार की अराजकता से दूर रहकर अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करने का आग्रह किया।

विघटनकारी ताकतों और फर्मी सूचनाओं से रहे सावधान- वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें अपने निहित स्वार्थों के चलते समाज में भ्रामक नैरेटिव गढ़ने और अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। युवाओं को यह पहचानना होगा कि कौन देश को

विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है और कौन समाज में वैमनस्य घोल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं की सत्यता परखने, तार्किक बनने और किसी के भी बहकावे में न आने पर जोर दिया।

'विकसित भारत 2047' की सबसे बड़ी पूंजी युवा शक्ति- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि देश वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के महान संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जब देश

आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब भारत वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक शक्ति सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने छात्रों से अनुशासन, शिक्षा, नवाचार और नैतिक मूल्यों को जीवन में आत्मसत करने की अपील की।

कॉलेज प्रबंधन ने किया विधायक का सम्मान- कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबंध समिति द्वारा मुख्य वक्ता विधायक अनुज शर्मा का शॉल व श्रीफ्ल भेंटकर आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष शकुंतला डीलेंद्र सेन, पूजा अश्वनी वर्मा, राबिन साहू, युनुस खान सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

ख़रोरा में ‘युवा संवाद’ संपन्न: विधायक अनुज शर्मा बोले— भ्रामक नैरेटिव और अराजकता फैलाने वालों को सबक सिखाएं युवा



रही हैं। युवाओं को ऐसी शक्तियों को पहचानना होगा। उन्होंने जोर दिया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर मिलने वाली किसी भी सूचना की सत्यता को परखे बिना विश्वास न करें; युवा तार्किक बनें और किसी के बहकावे में आने के

बजाय सही और गलत का अंतर समझें।

'विकसित भारत 2047' में युवा शक्ति की अहम भूमिका- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे

चक्रवात 'अर्नब' से फसलों को नुकसान: सीएम विष्णु देव साय ने दिए तत्काल सर्वे के निर्देश, RBC 6-4 के तहत मिलेगी राहत

सभी जिला कलेक्टरों को संवेदनशीलता और तत्परता से नुकसान का आकलन करने के आदेश

जनता के गोट- रायपुर -छत्तीसगढ़ में चक्रवात 'अर्नब' के प्रभाव से फसलों को हुए नुकसान को राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विशेष सर्वेक्षण कराएं और पात्र किसानों को जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संकट की इस घड़ी में अवदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत मिलेगी आर्थिक मदद- मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चक्रवात से प्रभावित खेतों में जाकर नुकसान का निष्पक्ष और त्वरित आकलन किया जाए। इसके बाद राज्यस्व पुस्तक परिपत्र (RBC 6-4) के निर्धारित नियमों एवं तय मानकों के आधार पर प्रभावित किसानों को सीधे मुआवजा राशि जारी की जाए।

सर्वे से लेकर वितरण तक न हो कोई देरी- प्रशासनिक मशीनरी को सख्त हिदायत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य से लेकर सहायता राशि के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। इस कार्य में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करे कि वास्तविक प्रभावित किसानों तक समय पर मदद पहुंच सके।

लिए युवाओं को अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में ढालना होगा।

आयोजन में ये रहे उपस्थित-समारोह के अंत में स्थानीय मंडल कार्यकर्ताओं ने मुख्य वक्ता विधायक अनुज शर्मा को शॉल व श्रीफ्ल भेंटकर आत्मीय अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, सविता चंद्राकर, सोना वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, सुनीता अनिल सोनी, रविशंकर वर्मा, अशोक सिन्हा, शशि वर्मा, सुमित सेन सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा मोर्चा के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे।